International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समकालीन भारत में किसान आंदोलन :– एक अध्ययन

संजय कुमार सहनी
नेट, शोधार्थी
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा

किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के आन्दोलन इस तथ्य के साक्षी हैं कि अमुक देश रोगग्रस्त है। एक बीमार समाज में विभिन्न समस्याओं का लेकर आन्दोलन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गयी है। ब्रिटिश शासन और सामन्तवादी समाज में किसानों, भूमिहीन श्रमिक, निर्धन, गरीब परिवारों की महिलाओं का शोषण किया गया है। उनसे श्रम तो करवाया गया पर मजदूरी इतनी कम दी जाती थी कि आजीवन जमींदार का गुलाम बना रहता था। कर्ज में डूबा किसान बंधुआ मजदूर बनकर जीता था। अन्ततः इन अत्याचारों के विरोध में किसानों ने मालिक के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। समकालीन समाज में किसान आन्दोलन आज भी जारी हैं। किसान, खेती और खेती से जुड़ी समस्याओं को लेकर स्वतंत्र भारत में आन्दोलन कर रहा है। नगर की अपेक्षा ग्रामीण समाज अविकसित है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में कुछ बड़े कृषकों के पास अत्याधिक भूमि है जबकि दूसरे भूमिहीन श्रमिक हैं अथवा वे बटाई पर काम करते हैं। कानूनी रूप से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई परन्तु व्यवहार में खेतिहर जमीन पर कुछ लोगों का ही कब्जा है। अब ये धनाढ़य वर्ग अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा जमा कर जमींदारी उन्मूलन कानून को मात देना चाहते हैं।[1]

दीपांकर गुप्ता का विचार है कि भारत में बुनियादी तौर पर दो प्रकार के किसानों का ध्रुवीकरण है। एक वे जो निर्धन कृषक श्रमिक और सीमान्त किसान हैं। दूसरे वे धनी मालिक किसान हैं जो अत्यधिक अनाज उत्पन्न करते हैं। ये धनाढ़य किसान पूंजीपति हैं जो कृषकों का शोषण करते हैं। इनके खेत बटाई पर चलते हैं अथवा दैनिक कार्य करते हैं।[2]

समकालीन भारतीय समाज में किसान आन्दोलन राजनैतिक दलों के द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन राजनैतिक दलों का सिद्धान्त, शोषण व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना है। ये किसान सभा, सी0पी0आई0एम0एल0 के द्वारा मुख्यतया आन्दोलन चलाये जाते हैं। इनका कार्य स्थल वहाँ हैं जहाँ इनकी सरकारें हैं अथवा सरकारें रही हैं अथवा जहाँ इनके दल का प्रभाव है– जैसे केरल, बंगाल, त्रिपुरा। दूसरे प्रकार के वे ग्रामीण किसान आन्दोलन है जो भारतीय किसान संघ द्वारा संचालित होते हैं। विशेष तौर से इनका पश्चिमी उत्तर–प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में काफी प्रभाव हैं। इन प्रदेशों में किसान आन्दोलन काफी बड़े स्तर पर हुए हैं। इनके द्वारा चलाये गये किसान आन्दोलनों की एक यह भी विशेषता रही है कि यह किसानों के हित और कल्याण की तो बात करते हैं लेकिन खेतिहर भूमिहीन, निर्धन श्रमिकों की उपेक्षा करते हैं। समकालीन किसान आन्दोलन की यह भी एक विशेषता है कि देश के सभी राज्यों में किसान आन्दोलन के मुद्दे अलग–अलग होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जो किसान आन्दोलन होते थे उनके लक्षण सामंतवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे। स्वतंत्र भारत में किसान आन्दोलन क्षेत्रीय व स्थानीय समस्याओं को लेकर किये जाते हैं। ये केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत किये जाते हैं। इनके सामान्य मुद्दे होते हैं जैसे गाँव को निरन्तर बिजली दी जाय। किसानों के लिये बिजली की दर कम हो। खाद के दाम कम किये जायें। उत्पाद के दाम निश्चित किये जायें। कम सूद पर किसानों को ऋण दिया जाये। इस प्रकार के किसान आन्दोलन को ''कुलक'' कहा जाता है। समय के साथ किसानों की संघीय शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इनकी शक्ति ने अंग्रेजों के भी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दांत खट्टे कर दिये। स्वतंत्र भारत में किसान संघ एक दबाव–समूह की तरह कार्य करता है। अपना दबाव बनाकर सरकार से मांगें पूरी कराने का प्रयास करता है। सरकार भी जानती है कि ग्रामीण खेतिहर समाज देश की प्रगति की रीढ़ है, तो वह उनके वोट बैंक का भी काम करती है।[3]

पश्चिम उत्तर प्रदेश के **महेन्द्र सिंह टिकैत** किसानों के बड़े नेता हैं। उन्होंने सदैव हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ रखने का काम किया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नारे को ही हथियार बनाया **''जय जवान, जय किसान''** उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बी0के0यू0 में हिन्दू और मुसलमानों के मध्य एकता बनाये रखी। वह अपना भाषण आरम्भ करने के पहले और खत्म करने के समय **''अल्लाह हो अकबर''** कहते हैं। **''हर हर महादेव''** कहते हैं। यह किसानों की राष्ट्रीय एकता का भी सन्देश देता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जमींदार ज्यादातर जाट और राजपूत हैं। टिकैत के अधिकांश किसान आन्दोलनों का आधार आर्थिक होता है। वे स्थानीय प्रशासन और शोषणकारी नीति के विरोध में नहीं होते, वे सीधे राज्य सत्ता से संघर्ष करते हैं। महेन्द्र सिंह टिकैत के फरवरी, **1988 जन आनदोलन** ने सम्पूर्ण भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके आन्दोलन का प्रदर्शन का केन्द्र दिल्ली का वोट क्लब था जहाँ 25 से 31 अक्टूबर तक उत्तर–प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने साथ मिलकर अभूतपूर्व धरना दिया। मुझे याद है इस धरने में लगभग 5,00,000 किसानों ने भाग लिया था। इस धरने से दिल्ली भी एक बार काँप उठी थी, किन्तु सरकार ने जब इनकी कुछ नहीं सुनी तो टिकैत को स्वतः धरना वापस लेना पड़ा। किसानों की मुख्य मांगें थीं – बिजली और खाद के दाम कम किये जायें। गन्ने का मुल्य 35 रु. प्रति क्विंटल निश्चित किया जाये। भारतीय किसान यूनियन की विशेषता है कि मालिक अपने खेतों पर स्वयं खेती करते हैं। महेन्द्र सिंह टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश के बेताज नेता कम से कम एक दशक से ज्यादा रहे हैं। अपने को यूनियन नेता क रूप में स्थापित भी किया है। वास्तव में, भारतीय किसान यूनियन का आरम्भ में कार्य क्षेत्र हरियाणा रहा है। 11 जुलाई, 1978 की कंजवाला गाँव की घटना ने तूल पकड़ लिया। इस घटना के पीछे किसी हरिजन व्यक्ति को 120 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई। यह जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इस घटना ने क्षेत्रीय किसानों को संगठित होकर आन्दोलन चालाने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में 1986 तक भारतीय किसान यूनियन ने अपनी जड़ें जमा ली थी और वह किसानों की समस्याओं का लेकर आन्दोलन करने लगे थे। जैसे 1986 में उसने बटौत जिला मेरठ में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर आन्दोलन किया। वास्तव में, समकालीन किसान आन्दोलन में महेन्द्र सिंह टिकैत और भारतीय किसान यूनियन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये इस आन्दोलन के फलस्वरूप 1988 में गेहूँ, जिसके भाव 10 रु. क्विंटल थे वे बढ़कर 183 रु. क्विंटल हो गया। ठीक इसी प्रकार बिजली की दर 30 रु. से घटकर 20 रु. प्रति हार्सपावर हो गई। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी।[4]

1969–70 में तमिलनाडू में एक किसान संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था तमिलनाडु विवासैपगल संगम। इस संगठन के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगे रखी। उनकी माँग थी बिजली की दरें कम की जायें। कर्ज की वसूली स्थगित की जाय। इन्हीं मांगो को लेकर विवासैपगल ने 1972 में आन्दोल छेड़ा। 1979 में महाराष्ट्र में शरद जोशी ने प्याज उत्पादकों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन किया। इसी प्रकार 1946–47 के मध्य तेभागा आन्दोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें लगान देने वाले किसानों ने सामन्तवादियों का डट कर विरोध किया। 1970 का भूमि हड़पों आन्दोलन कम महत्वपूर्ण नहीं था। इस आन्दोलन का नेतृत्व पहले कांग्रेस ने फिर बाद में समाजवादियों ने किया। 20वीं शताब्दी का तेलंगाना आन्दोलन अपना सानी नहीं रखता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक किसान आन्दोलन हुए किन्तु हरित क्रान्ति काल में किये गये सरकारी सुधार कानूनों के फलस्वरूप जो आन्दोलन हुए वे काफी महत्वपूर्ण थे। दिसम्बर 1969 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्तमान कृषि संबंधी तनाव के कारण और स्वरूप पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1966 से 1969 तक के किसान संघर्षों का चार प्रकार के प्रश्नों से संबंध रहा जो इस प्रकार है–

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

1. बिहार, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के आन्दोलनों में दो मांगें मुख्य थी – पैदावार में उचित साझा और जिन खेतों पर वे खेती करते हैं उन पर उनके खेती करने के स्थायी अधिकार की गारन्टी।
2. केरल के अलेप्पी जिले, तमिलनाडु के तन्जौर जिले, आन्ध्र प्रदेश पूर्व और पश्चिम गोदावरी, नेलोर और गुन्टर जिलों आदि राज्यों में हुए खेतिहर मजदूरों के आन्दोलनों और हड़तालों में उनकी प्रमुख माँग थी कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाय।
3. असम, आन्ध्र–प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य–प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में भूमिहीन और निम्न श्रेणी के गरीब किसानों ने जगह–जगह घूम–घूम कर सत्याग्रह किये और जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया, उनके पीछे उनकी प्रमुख माँग थी कि ग्रामों में पड़ी भूस्वामियों के अतिरिक्त अर्थात् उच्चतम सीमा से अधिक भूमि, गांव समाजों और जंगलात विभाग की फालतू जमीनों को उनमें वितरित किया जाय।
4. आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में हुए बलवों और बिहार के छोटा नागपुर तथा उड़ीसा के काड़ापुर जिले में हो रहे आन्दोलनों के पीछे यह मुख्य माँग थी कि सूदखोर सेठ साहूकार और बाहरी भूस्वामियों के शोषण से कबायली लोगों की रक्षा की जाय।[5]

पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि महेन्द्र सिंह टिकैत किसानों के नेता माने जाते हैं तो महाराष्ट्र में शरद जोशी। इन्होंने ''शेतकारी'' संगठन की स्थापना करके किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के किसानों का अपना महत्व है। वे सामान्यतया सीमान्त किसानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। महाराष्ट्र में पाटिल अथवा देशमुख का मुख्य स्थान है। 1948 में सहकारी संगठन के द्वारा वे कार्य क्षेत्र में उतरे। शरद जोशी न तो मराठी थे और न वे कृषक समाज की पृष्ठभूमि लेकर किसानी समाज में उतरे थे। फिर भी वे किसानों के नेता थे। मराठियों ने ''शेतकारी संगठन'' की गतिविधियों के समझाने के पश्चात वे शरद जोशी को अपना समर्थन देने लगे और शरद जोशी महाराष्ट्र में किसानों के बड़े और प्रभावशाली नेता माने जाने लगे। शरद जोशी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे किसानों की समस्याओं के समय सदैव उपलब्ध रहे। आन्दोलन को दिशा दी और उसका नेतृत्व किया। इन्होंने महाराष्ट्र के टुकड़ों–टुकड़ों में बटे किसानों को एकजुट किया। एक मंच पर लाये। किसान संगठन को ताकत भी दी और शक्तिशाली भी बनाया। शरद जोशी ने अपने एक राजनैतिक दल ''स्वतन्त्र भारत'' की मई 1994 में स्थापना की।[6] महाराष्ट्र में मराठियों की कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत की संख्या है। महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य समस्यायें हैं – किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाय। कपास के उत्पाद को अधिक से अधिक सरकार खरीदे क्योंकि सरकार मात्र 20 प्रतिशत ही क्रय करती है। 18 अप्रैल, 1988 को जलगांव में ''शेतकारी'' संगठन ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली के द्वारा सरकार से यह मांग की गई कि गांव में कर्ज वसूली का विरोध किया गया। गाँव में भयंकर सूखा पड़ जाने के कारण लगान व कर्ज न लिया जाय। सूखा पड़ने से हजारों किसान हाशिये पर आ गये थे। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। उसने 217 करोड़ रू. का किसानों का कर्ज माफ कर दिया।[7]

किसान आन्दोलनों से कुछ नतीजे निकाले जा सकते हैं। किसान जिसकी भूमि और खेती ही सब कुछ है, ग्रामीण समाज का अधिकांश कृषक जिसके पास बहुत थोड़ी भूमि

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है, वह बटाई पर काम करता है। भूमिहीन श्रमिकों की दशा शोचनीय है। इसी तरह खेती से जुड़े असंख्य परिवार हाशिये पर हैं। ग्रामीण समाज का सामन्तवादी ढ़ांचा गिर गया। जमींदारी का उन्मूलन हुआ। कानून ने किसानों को कुछ राहत दी। किन्तु आज भी नये चेहरों में नये युग के धनाढ़य भू माफिया ग्रामीण और खेतों पर कब्जा जमाए हैं। शोषण, उत्मीड़न और अत्याचार आज भी किसानों का बड़े धनाढ़य किसानों द्वारा हो रहा है। ये वे तथाकथित किसान हैं जो स्वयं खेती नहीं करते बल्कि बटाई पर खेती करवाते हैं। ये भूमिहीन श्रमिकों को कम से कम पारिश्रमिक देकर किसानी कराते हैं।

ग्रामीण समाज की जातीय व्यवस्था एवं संरचना सामान्यतः पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, दुर्बल वर्ग के लिये अभिशाप बन चुकी है। छोटी निर्धन जातियों का आज भी शोषण किया जाता है। छोटी, अशिक्षित असवर्ण जातियों में अभी ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो इनकी समस्याओं का आधार बनाकर आन्दोलन चलाये सच यह भी है कि इन्हें किसान माना ही नहीं जाता। इन्हें भूमिहीन श्रमिक कहा जाता है। इसे विडम्बना ही कहेंगे।

पानी, बिजली, खाद और ऋण को लेकर आज भी किसान आन्दोलन करते हैं। इन सब कमियों के बावजूद भी आज कृषि व्यवसाय के ढ़ाँचे में अनेक सुधार के सुखद परिवर्तनों को सहज ही देखा जा सकता है। जैसे अच्छी से अच्छी खाद किसानों को उपलब्ध है। खेती के समय अधिक समय तक किसानों को बिजली दी जाती है। खेती के लिये ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों की फसल को उचित मूल्य पर क्रय करती है। खेती के नये–नये तरीकों की जानकारी किसानों को दी जाती है। यही कारण है कि भारत अन्न के मामले में आत्म निर्भर बन चुका है। ग्रामीण समाज की महाजनी–संस्कृति किसानों को बैंक से ऋण मिल जाने के कारण लगभग समाप्त हो चुकी है। इस दृष्टि से महाजन, सूदखोर और धनाढ़य लोग किसानों का न तो शोषण कर पाते हैं और न बन्धुआ श्रमिक ही बना पाते हैं। ग्रामीण समाज में बन्धुआ श्रमिकों की प्रथा लगभग समाप्त हो गयी है।

ग्रामीण और कृषक समाज में राजनैतिक और जातिगत जागरूकता में, स्वतंत्रता के पश्चात अत्यधिक वृद्धि हुई। किसान अब अपना भला बुरा समझने लगे हैं। विभिन्न जातियों के अलग–अलग राजनैतिक नेता हो गए हैं जो अपनी जाति के किसानों के लिये आन्दोलन करते है, संघर्ष करते हैं। इस प्रकार के किसान आन्दोलनों की प्रकृति छोटे समय की होती है। स्थानीय और क्षेत्रीय किसान भी आन्दोलन करते हैं। इसीलिये ये अल्पायु के आन्दोलन होते हैं। फुलझड़ी की तरह चमक कर बुझ जाते हैं।

किसान आन्दोलन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसानों का अब जमींदार या धनाढय किसान शोषण और उत्पीड़न इस स्तर पर नहीं कर पाता है जिस स्तर पर वह ब्रिटिश शासन में किया करता था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिये अनेक योजनायें बनायी हैं और साथ ही वह ग्रामीण समाज और कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिये वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 2, February 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संदर्भ सूची :–

1. आनंद चक्रवर्ती – संपादित, एण्डरे बेटली, इब्यूलिटी एण्ड इन्कयूलिटी, पृष्ठ – 158
2. दीपांकर गुप्ता – सम्पादित, घनश्याम शाह, सोशल मूवमेन्ट एण्ड द स्टेट, पृष्ठ – 191
3. एम0 ए0 रसूल – हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा
4. महेन्द्र प्रताप – उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन
5. दिपांकर गुप्ता – शोसल मूवमेंट एण्ड द स्टेट, सम्पादित घनश्याम शाह
6. दिपांकर गुप्ता – शोसल मूवमेंट एण्ड द स्टेट, सम्पादित घनश्याम शाह
7. के0 रंगाराव – शोसल मूवमेंटस इन इंडिया, सम्पादित एम0 एस0 ए0 राव